

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 5858/2023

गोपाल सिंह पुत्र उत्तम सिंह वर्मा, निवासी मकान संख्या 44, अमृत सागर नगर,  
थाना कोटला मुबारकपुर, दक्षिण दिल्ली।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, लोक अभियोजक के माध्यम से
2. सिद्धार्थ गुप्ता पुत्र स्व. श्री राकेश गुप्ता, निवासी ए 629, केलगिरी रोड, मालवीय नगर, जयपुर शहर (पूर्व), जयपुर (राजस्थान)

----प्रतिवादी

संबंधित

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 5840/2023

आलोक सिंह पुत्र श्री नागेश्वर सिंह, निवासी बी-213, पालम एक्सटेंशन, रामपाल चौक  
के पास, सेक्टर-7, द्वारका, दक्षिण पश्चिम, दिल्ली।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, लोक अभियोजक के माध्यम से
2. सिद्धार्थ गुप्ता पुत्र श्री राकेश गुप्ता, निवासी ए 629, केलगिरी रोड, मालवीय नगर, जयपुर सिटी (पूर्व), जयपुर (राजस्थान)

----प्रतिवादी

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 5859/2023

गौरव मल्होत्रा पुत्र श्री यशपाल मल्होत्रा, निवासी मकान संख्या 108, अशोक विहार-  
III, गुडगांव।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, लोक अभियोजक के माध्यम से
2. सिद्धार्थ गुप्ता पुत्र श्री राकेश गुप्ता, निवासी ए 629, केलगिरी रोड, मालवीय नगर, जयपुर शहर (पूर्व), जयपुर (राजस्थान)

-----प्रतिवादी

-----  
याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री एस.पी. सिंह चौहान,  
श्री भंवर सिंह चौहान  
प्रतिवादी के लिए : श्री लक्ष्मण मीना, पीपी  
शिकायतकर्ता के लिए : श्री एस.एस. होरा सहित  
श्री अनुज जैन  
श्री संजय शर्मा, एसीपी मालवीय नगर, जयपुर  
-----

माननीय न्यायमूर्ति सुदेश बंसल

निर्णयनिर्णय सुरक्षित

5 दिसंबर 2023

निर्णय सुनाया गया

3 जनवरी 2024

न्यायालय द्वाराप्रकाशनीय

1. धारा 482 सीआरपीसी के तहत ये तीन अलग-अलग आपराधिक विविध याचिकाएं पुलिस स्टेशन मालवीय नगर, जिला जयपुर में आईपीसी की धारा 420, 406 और 120-बी के तहत अपराधों के लिए दर्ज एफआईआर संख्या 361/2023 को रद्द करने के लिए दायर की गई हैं, साथ ही इसके बाद की सभी कार्यवाहियों को भी रद्द करने के लिए, जिसमें याचिकाकर्ताओं को आरोपी व्यक्तियों के रूप में नामित किया गया है, जो कथित तौर पर ऐसे अपराधों में शामिल हैं।

2. चूंकि तीनों याचिकाएं एक ही एफआईआर से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए दोनों पक्षों के वकीलों की सहमति से, तीनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की गई है और इस सामान्य निर्णय से निर्णय लिया जाएगा।

3. वर्तमान याचिकाओं से निपटने के लिए विचार किए जाने वाले प्रासंगिक तथ्य, जैसा कि रिकॉर्ड से सामने आता है और दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा दिए गए तर्क, संक्षेप में, निम्नानुसार हैं:

(I) पक्षों के बीच विवाद किलोमीटर-125, दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे (राष्ट्रीय राजमार्ग-4), ग्राम पिनान, जिला अलवर (राजस्थान) स्थित एक अचल संपत्ति के संबंध में है, जिसके संबंध में जी एंड जी रोड आइलैंड डेवलपर्स एलएलपी, इसके नामित भागीदार श्री सिद्धार्थ गुप्ता (प्रतिवादी संख्या 2) और याचिकाकर्ताओं के बीच दिनांक 16.03.2023 को एक उप-पट्टा समझौता हुआ था। इस उप-पट्टा समझौते के तहत, संपत्ति का कब्जा कथित तौर पर याचिकाकर्ताओं को रजवाड़ा हॉल के नाम और शैली में एक शाकाहारी रेस्टोरेंट चलाने के उद्देश्य से, शुरुआत में केवल एक महीने की अवधि के लिए, 16.03.2023 से 15.04.2023 तक, दिया गया था।

(II) बाद में, दिनांक 11.04.2023 के पत्र के माध्यम से, पट्टाकर्ता द्वारा उप-पट्टा समझौते की अवधि अगले 21/2 महीने अर्थात् 30.06.2023 तक बढ़ा दी गई थी, इस शर्त के साथ कि रेस्तरां के लिए उप-पट्टा किराया रेस्तरां में खाद्य पदार्थों की बिक्री से कुल राजस्व/बिक्री आय का 30% (जीएसटी को छोड़कर) होगा और उप-पट्टा किराया अगले महीने के पहले सप्ताह तक या उससे पहले भुगतान किया जाएगा; राजस्व हिस्सेदारी के भुगतान में देरी के मामले में, भुगतान 18% प्रति वर्ष ब्याज के साथ किया जाएगा। यह बताया गया है कि विवादित संपत्ति सहित परिसर वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) का है और इसे एनएचएआई द्वारा पाथ कंपनी को पट्टे पर दिया गया था, फिर बदले में, शिकायतकर्ता-प्रतिवादी संख्या 2 ने पाथ कंपनी से कुछ परिसर पट्टे पर ले लिया और फिर पट्टा शर्तों की स्वीकार्य शर्तों के भीतर, शिकायतकर्ता-प्रतिवादी संख्या 2 ने

विवादित संपत्ति का हिस्सा याचिकाकर्ताओं को उप-पट्टे पर, एक छोटी अवधि के लिए सौंप दिया, जिसे केवल परीक्षण के आधार पर बताया गया है।

(III) शिकायतकर्ता-प्रतिवादी संख्या 2 के अनुसार, उसे एनएचआई के साथ-साथ पाथ कंपनी को नियमित आधार पर उप-पट्टा समझौते के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा देय राजस्व की राशि से राजस्व का भुगतान करना आवश्यक है, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने उप-पट्टे की अवधि बढ़ाते समय राजस्व का भुगतान करना बंद कर दिया है, जो रेस्तरां की कुल बिक्री आय का 30% (जीएसटी को छोड़कर) होने पर सहमत हुआ था और इस प्रकार, वास्तव में याचिकाकर्ता सहमत राजस्व राशि का भुगतान किए बिना विवादित संपत्ति के कब्जे का आनंद ले रहे हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि ऐसी स्थिति में, शिकायतकर्ता को याचिकाकर्ताओं को दिनांक 01.07.2023 का एक नोटिस देना होगा, जिसके माध्यम से उन्हें सूचित किया गया था कि याचिकाकर्ताओं का प्रदर्शन असंतोषजनक पाया गया है और साथ ही उन्होंने विस्तारित उप-पट्टा समझौते के नियमों और शर्तों का पालन नहीं किया है, इसलिए, याचिकाकर्ताओं को उप-पट्टा परिसर खाली करने और 30.06.2023 की अवधि तक कथित रूप से उन पर बकाया 26,79,750/- रुपये के राजस्व का बकाया भुगतान करने के लिए कहा गया था।

(IV) शिकायतकर्ता के अनुसार, दिनांक 01.07.2023 का ऐसा नोटिस याचिकाकर्ताओं को विधिवत रूप से दिया गया था, हालाँकि, इसका कभी जवाब नहीं दिया गया/प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। बकाया राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान करने और उप-पट्टा परिसर का खाली कब्जा सौंपने के लिए बोली लगाने पर, याचिकाकर्ताओं ने शिकायतकर्ता के साथ दुर्यवहार करना शुरू कर दिया ऐसी विवश परिस्थितियों में, शिकायतकर्ता को 16.08.2023 को कथित एफआईआर दर्ज करने के

लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमें याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप लगाया गया कि उनका शुरू से ही शिकायतकर्ता को धोखा देने का इरादा था और उनका राजस्व हिस्सा चुकाने का कोई इरादा नहीं था। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने विवादित संपत्ति पर कब्जा बेईमानी से हड़पने के द्वेषपूर्ण इरादे से हासिल किया। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और शुरू से लेकर अब तक उनकी पूरी कार्रवाई जितनी धोखाधड़ीपूर्ण है, उतनी ही मिलीभगत भी है। 31.07.2023 की अवधि तक राजस्व का बकाया 77 लाख रुपये से अधिक जमा हो गया है, जिसका भुगतान नहीं किया गया है और न ही बार-बार अनुरोध के बावजूद विवादित संपत्ति का कब्जा सौंपा गया है, इसलिए धोखेबाज और चूककर्ता याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

(V) शिकायतकर्ता के विद्वान वकील ने इस न्यायालय का ध्यान, पास ही स्थित एक अन्य होटल टोकस के प्रबंधन द्वारा, वर्तमान में होटल रजवाड़ा दरबार का प्रबंधन और प्रभार संभाल रहे व्यक्तियों के विरुद्ध, पुलिस स्टेशन राजगढ़, जिला अलवर में 24.10.2023 को दर्ज एक अतिरिक्त एफआईआर संख्या 591/2023 की ओर आकर्षित किया है। यह एफआईआर यह दर्शाने के लिए दायर की गई है कि वास्तव में, याचिकाकर्ताओं ने होटल रजवाड़ा का प्रभार, प्रबंधन और कब्जा कुछ असामाजिक तत्वों को सौंप दिया है, जो कानून को अपने हाथ में लेने के आदी हैं। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि आरोपी याचिकाकर्ताओं का शुरू से ही शिकायतकर्ता के साथ समझौते करने का एक कपटपूर्ण और बेईमान इरादा था, इसलिए उन्होंने शिकायतकर्ता को धोखे से परिसर का कब्जा उन्हें सौंपने के लिए प्रेरित किया। याचिकाकर्ता धोखाधड़ी का अपराध करने और शिकायतकर्ता की संपत्ति को बेईमानी से हड़पने के लिए प्रथम दृष्टया दोषी हैं, इसलिए तथ्यों और परिस्थितियों की

समग्रता में, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 405, 420 और 120-बी के तहत अपराध करने का स्पष्ट मामला बनता है, इसलिए, उनके आपराधिक कृत्यों और धोखाधड़ी के लिए उन पर मुकदमा चलाने के लिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

4. आरोपी याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि समग्र रूप से आक्षेपित एफआईआर की सामग्री के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि पक्षों के बीच एक लिखित अनुबंध था जिसके तहत, विचाराधीन संपत्ति का कब्जा शाकाहारी रेस्तरां चलाने के लिए याचिकाकर्ताओं को वैध रूप से सौंपा गया था। यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता राजस्व के अपने हिस्से का भुगतान कर रहे हैं और एफआईआर में यह गलत तरीके से कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ राजस्व के बकाया के 77 लाख रुपये से अधिक 31.07.2023 तक देय हैं। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने बहस के दौरान, खातों के विवरण को संदर्भित करने की मांग की, ताकि यह दिखाया जा सके कि 22.06.2023 तक समय-समय पर, याचिकाकर्ताओं ने एनईएफटी के माध्यम से शिकायतकर्ता के खाते में कुल 78,29,335/- रुपये का भुगतान किया है। विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया है कि यदि तर्कों के लिए यह मान भी लिया जाए कि याचिकाकर्ताओं द्वारा राजस्व हिस्सेदारी की पूरी राशि का भुगतान न करने के संबंध में पक्षों के बीच कुछ विवाद है, तो भी देय राशि की वसूली का कोई उपाय, यदि कोई हो, शिकायतकर्ता के पास उपलब्ध है। विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान दिनांक 16.03.2023 के उप-पट्टा समझौते के प्रासंगिक खंड संख्या 6 की ओर आकर्षित किया है, जिसमें विवाद समाधान मंच के बारे में कहा गया है कि पक्षों के बीच सभी प्रकार के विवादों और मतभेदों को दो मध्यस्थों के पास भेजा जाएगा और उनके द्वारा निपटाया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक पक्ष द्वारा एक मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। संक्षेप में,

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क यह है कि राजस्व के बकाया या कब्जे की गैर-सुपुर्दगी या उप-पट्टा समझौते की शर्तों के उल्लंघन का विवाद, चाहे जो भी हो, पक्षों के बीच विवाद की प्रकृति पूरी तरह से दीवानी है और शिकायतकर्ता ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से यहां एफआईआर दर्ज करके इस तरह के दीवानी विवाद को आपराधिक रंग देने की कोशिश की है।

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा सिविल जज, रेनी, जिला अलवर के समक्ष प्रतिवादी नंबर 2 शिकायतकर्ता के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक सिविल मुकदमा भी दायर किया गया है, जिसमें शिकायतकर्ता ने स्वयं उप-पट्टा समझौते में शामिल मध्यस्थता खंड का सहारा लिया है और आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के साथ पठित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद संक्षेप में "ए एंड सी अधिनियम, 1996") की धारा 8 के तहत एक आवेदन दिया है, जो कि सिविल कोर्ट के समक्ष शिकायत को खारिज करने के लिए है और एक दलील दी है कि विवाद को ए एंड सी अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थता द्वारा सुलझाया जाना है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इस तरह के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों में, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोपित एफआईआर का पंजीकरण और पुलिस की सहायता से याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करना, एक विवाद में जो पूरी तरह से नागरिक प्रकृति का है, कानून में अनुचित और अनुचित है जितना कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। पुलिस अधिकारियों के पास ऐसी एफआईआर दर्ज करने और जांच के लिए आगे बढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, हालांकि, याचिकाकर्ताओं को सीआरपीसी की धारा 41-ए के तहत नोटिस जारी किए गए थे, जिनका विधिवत जवाब भी दिया गया है, फिर भी शिकायतकर्ता के प्रभाव में, पुलिसकर्मी याचिकाकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं और वास्तव में, शिकायतकर्ता, याचिकाकर्ताओं पर वर्तमान एफआईआर का

दबाव डालकर, याचिकाकर्ताओं से संबंधित संपत्ति का कब्जा वापस लेना चाहता है, जबकि याचिकाकर्ता वैध कब्जे में हैं और नियमित आधार पर अपने राजस्व हिस्से का भुगतान कर रहे हैं। इसलिए, यह प्रार्थना की गई है कि कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए और न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, यह वांछनीय और आवश्यक है कि यह न्यायालय सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करके पुलिस द्वारा शुरू की गई सभी सहायक कार्यवाहियों के साथ आरोपित एफआईआर को रद्द कर दे।

अपने तर्कों के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने निम्नलिखित निर्णयों का हवाला दिया है:

- (i) दलीप कौर बनाम जगनार सिंह [(2009) 14 एससीसी 696];
- (ii) सरबजीत कौर बनाम पंजाब राज्य [(2023) 5 एससीसी 360];
- (iii) विजय कुमार घई बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [(2022) 7 एससीसी 124];
- (iv) अनिल महाजन बनाम भोर इंडस्ट्रीज लिमिटेड [(2005) 10 एससीसी 228];
- (v) उमा शंकर गोपालिका बनाम बिहार राज्य [(2005) 10 एससीसी 336] और;
- (vi) सतीशचंद्र रतनलाल शाह बनाम गुजरात राज्य [(2019) 9 एससीसी 148]।

6. इसके विपरीत, विद्वान सरकारी वकील ने वर्तमान याचिकाओं का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि एफआईआर की सामग्री और पुलिस द्वारा अब तक की गई जांच से, याचिकाकर्ताओं द्वारा एक संज्ञेय अपराध किया गया है। जांच के दौरान, याचिकाकर्ताओं को धारा 41-ए सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने जांच में सहयोग नहीं किया है और वे पेश नहीं हुए हैं। जांच के दौरान, यह पता चला है कि उप-पट्टा समझौते के बकाया के रूप में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ 76,19,619/- रुपये की राशि बकाया है और याचिकाकर्ता

फरार हैं, हालांकि स्थानीय अपराधियों की मदद से रेस्तरां चलाकर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जांच पूरी करने के लिए, याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी आवश्यक है, क्योंकि उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 406 और 120-बी के तहत अपराध किए गए हैं।

7. शिकायतकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने अपने प्रेरक और मजबूत प्रस्तुतियों के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष यह स्थापित करने का प्रयास किया कि शिकायतकर्ता के लिए केवल एक सिविल उपाय की उपलब्धता उसे आपराधिक कार्यवाई शुरू करने से नहीं रोकती है, क्योंकि आरोपी याचिकाकर्ताओं का शुरू से ही धोखाधड़ी और बेईमानी का इरादा था और उन्होंने शिकायतकर्ता को परिसर का कब्जा उन्हें सौंपने के लिए प्रेरित और धोखा दिया और उसके बाद, याचिकाकर्ताओं ने बेईमानी से संपत्ति को अपने उपयोग के लिए गबन कर लिया। यह आग्रह किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए मामलों की श्रृंखला में, यह माना गया है कि एक सिविल दावे को जन्म देने वाले तथ्य भी आपराधिक अपराध की श्रेणी में आ सकते हैं और केवल इसलिए कि एक सिविल दावा पोषणीय है या पक्षों के बीच एक मध्यस्थता समझौता मौजूद है, यह अपने आप में आपराधिक कार्यवाही को विफल नहीं करता है। विद्वान वकील ने दृढ़ता से कहा कि विवादित परिसर एक सार्वजनिक परिसर है, जो एनएचआई से संबंधित है, और शुरू से ही याचिकाकर्ताओं ने अपने निजी लाभ के लिए इसका उपयोग करने के लिए संपत्ति का दुरुपयोग करने की कोशिश की, यहां तक कि संपत्ति को केवल परीक्षण के आधार पर अल्पावधि के लिए दिया गया था, लेकिन याचिकाकर्ताओं का शुरू से ही शिकायतकर्ता को धोखा देने का धोखाधड़ी का इरादा था और उन्होंने सहमत राजस्व का बकाया भी नहीं चुकाया है, जो अब एक करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। याचिकाकर्ताओं का इरादा शुरू से ही नेक और निष्पक्ष

नहीं था और अब उन्होंने क्षेत्र में भय का माहौल बनाने के लिए अन्य दोषियों को शामिल किया है। याचिकाकर्ताओं को पुलिस द्वारा प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है और उनके कृत्यों और कार्यों के आधार पर, उनके खिलाफ धोखाधड़ी और विश्वासघात का अपराध बनता है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं के आचरण पर विचार उन्होंने दलील दी कि कानून का प्रस्ताव यह है कि उच्च न्यायालय को अपनी शक्तियों का प्रयोग असाधारण रूप से और संयम से करना चाहिए, ताकि एफआईआर को रद्द किया जा सके, वह भी उस पर जाँच पूरी होने से पहले। पुलिस एजेंसी द्वारा आक्षेपित एफआईआर पर जाँच जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं है और इसलिए, इस स्तर पर वर्तमान याचिकाओं को खारिज किया जाना चाहिए।

अपने तर्कों के समर्थन में, शिकायतकर्ता-प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान वकील ने निम्नलिखित निर्णयों का हवाला दिया है:

- (i) ट्रिस्न्स केमिकल इंडस्ट्री बनाम राजेश अग्रवाल [(1999) 8 एससीसी 686];
- (ii) कमलादेवी अग्रवाल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [(2002) 1 एससीसी 555];
- (iii) उड़ीसा राज्य बनाम उज्ज्वल कुमार बर्धन [(2012) 4 एससीसी 547];
- (iv) प्रीति सराफ बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य [(2021) एससीसी ऑनलाइन 206] और;
- (v) लालमुनि देवी बनाम बिहार राज्य [(2001) 2 एससीसी 17]

8. दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों द्वारा ऊपर उल्लिखित तर्कों के अलावा, दोनों पक्षों ने कुछ दस्तावेजों की प्रतियां भी रिकॉर्ड में रखी हैं, जिनमें पक्षों के बीच निष्पादित उप-पट्टा समझौते, शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया दिनांक 11.04.2023 का विस्तार पत्र, जी एंड जी रोड आइलैंड डेवलपर्स एलएलपी की ओर से शिकायतकर्ता द्वारा जारी दिनांक 01.07.2023 का नोटिस, एक अन्य एफआईआर संख्या

591/2023, याचिकाकर्ताओं द्वारा सीआरपीसी की धारा 41-ए के तहत नोटिस का उत्तर, याचिकाकर्ताओं की ओर से शिकायतकर्ता के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दीवानी मुकदमा और ए एंड सी अधिनियम, 1996 की धारा 8 के तहत आवेदन, साथ ही आदेश 7 नियम 11 सीपीसी, शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत आदि शामिल हैं। उपर्युक्त दस्तावेज, दोनों पक्षों के बीच निर्विवाद होने के कारण तथा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से, दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वन्दितापूर्ण तर्कों पर विचार करने के अतिरिक्त, विचार में लिए गए हैं।

9. वर्तमान मामलों में तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर विचार करने से पहले, शुरू में, उच्च न्यायालय के दायरे और दायरे पर चर्चा करना उचित होगा, धारा 482 Cr.PC के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, विशेष रूप से जांच के स्तर पर एफआईआर को रद्द करने के संबंध में। इस मुद्दे पर, यह अवलोकन करना पर्याप्त है कि विधि के प्रस्ताव को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में अपने एन-संख्या के निर्णयों के माध्यम से विराम दिया गया है, जिसके तहत यह तय किया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्तियां, जो धारा 482 Cr.PC के आधार पर संरक्षित हैं और मान्यता प्राप्त हैं, बहुत सावधानी और चौकसी के साथ प्रयोग की जानी चाहिए, वह भी दुर्लभतम मामलों में, जहां तथ्यों और सामग्री की बारीकी से जांच पर रिकॉर्ड पर लाया गया है, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करना आवश्यक है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि एफ. आई. आर. की सामग्री कोई विश्वकोश नहीं है, तथापि, उसमें लगाए गए आरोपों को पढ़ा जाना चाहिए, कुछ भी जोड़े या घटाए बिना और पुलिस द्वारा एकत्र की गई या पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई

अन्य सामग्री/साक्ष्य, यदि निर्विवाद है, तो इस पर भी विचार किया जा सकता है कि क्या सभी तथ्य संचयी रूप से एक संज्ञेय अपराध को जन्म देते हैं, जिसकी जांच जांच एजेंसी के हाथों में की जानी चाहिए या न्यायालय के समक्ष आपराधिक अभियोजन के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस स्तर पर उच्च न्यायालय को मामले में बारी-बारी से जांच करने या प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों की शुद्धता/सच्चाई की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 482 Cr.PC के तहत उच्च न्यायालय में निहित शक्तियां काफी व्यापक हैं और, यदि विवेकपूर्ण और सावधानीपूर्वक प्रयोग किया जाता है, तो लगभग सभी स्थितियों का ध्यान रखा जा सकता है, जहां आपराधिक कार्यवाही की शुरुआत/निरंतरता पक्ष के उत्पीड़न या उत्पीड़न के बराबर पाई जाती है, यहां तक कि एफआईआर पर जांच के चरण में या शिकायत पर जांच या किसी भी परीक्षण या आपराधिक कार्यवाही में। इस प्रकार के असाधारण मामलों में, उच्च न्यायालय धारा 482 Cr.PC के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग एफआईआर और जांच को रद्द करने और आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने के लिए कर सकता है, यदि कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग का मामला स्पष्ट रूप से बनता है।

कानून के ऐसे प्रस्ताव को बल देने और उसे शक्ति प्रदान करने के लिए, जैसा कि ऊपर देखा गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों में से कुछ प्रसिद्ध निर्णयों का संदर्भ पर्याप्त होगा; i) आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य [एआईआर (1960) एससी 866], ii) हरियाणा राज्य बनाम चौधरी भजनलाल [(1992) सप्लीमेंट (1) एससीसी 335] (पैरा संख्या 102), iii) मेसर्स नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य [एआईआर (2021) एससी 1918] [पैरा संख्या 23 (xiv)], iv) परबतभाई अहीर @ परबतभाई भीमसिंहभाई करमूर बनाम गुजरात

राज्य [(2017) 9 एससीसी 641] (पैरा संख्या 16) और, v) प्रीति सराफ बनाम।  
एनसीटी दिल्ली राज्य [(2021) एससीसी ऑनलाइन 206 (पैरा संख्या 23 से 28)]।

10. वर्तमान मामलों के गुण-दोष की बात करें तो, आक्षेपित एफआईआर की विषय-वस्तु के अवलोकन से, एक निर्विवाद तथ्य सामने आता है कि फर्म जी एंड जी रोड आइलैंड डेवलपर्स एलएलपी के साझेदारों, जिसमें शिकायतकर्ता-प्रतिवादी नंबर 2 भी शामिल है, ने जानबूझकर और स्वेच्छा से रजवाड़ा रेस्तरां के मालिकों, याचिकाकर्ताओं को विश्राम क्षेत्र का कब्जा सौंप दिया, ताकि वे हॉल में एक रेस्तरां को परीक्षण के आधार पर शुरू में 16.03.2023 से 15.04.2023 तक की अवधि के लिए उप-पट्टे पर चला सकें और बाद में, उप-पट्टे की एक महीने की अवधि 30.06.2023 तक बढ़ा दी गई। यह पक्षों के बीच एक निर्विवाद तथ्य है कि उप-पट्टे के नियमों और शर्तों को शामिल करते हुए एक लिखित अनुबंध परीक्षण के आधार पर निष्पादित किया गया था और उसके बाद, जी एंड जी रोड आइलैंड डेवलपर्स एलएलपी के लिए और उसकी ओर से अधिकृत नामित साझेदार होने के नाते, शिकायतकर्ता श्री सिद्धार्थ गुप्ता द्वारा 11.04.2023 के उप-पट्टा विलेख विस्तार पत्र के माध्यम से लिखित रूप में उप-पट्टा अवधि भी बढ़ा दी गई थी। दिनांक 11.04.2023 का विस्तार पत्र, एक निर्विवाद दस्तावेज होने के नाते, जिसे रिकॉर्ड में रखा गया है, निम्नानुसार है:

“विषय: दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे-4), गांव पिनान, जिला अलवर, राजस्थान, पिनकोड-301413, किमी 125 पर स्थित ब्लॉक नंबर 3 के हॉल नंबर 1 में आरएचएस भाग के उप-पट्टे का अगले ढाई महीने के लिए विस्तार/नवीनीकरण, जो शाकाहारी रेस्तरां चलाने के लिए 30 जून 2023 को समाप्त होगा।

प्रिय महोदय,

आपके मौखिक टेलीफोनिक अनुरोध और व्यक्तिगत बैठक के अनुसार और संशोधित राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्था के आपके प्रस्ताव के आधार पर, हम उप-लीज विलेख को अगले ढाई महीने यानी 30/06/2023 तक बढ़ाते हैं, जो मूल रूप से 16/03/2023 को एक महीने की प्रारंभिक अवधि के लिए निष्पादित किया गया था, ताकि हम आपसी सहमति से शाकाहारी रेस्तरां चलाने के लिए "ब्लॉक नंबर 3 के हॉल नंबर 1 के आरएचएस भाग, किलोमीटर 125, दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे (राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे-4), गाँव पिनान, जिला अलवर, राजस्थान, पिन कोड-301413" पर स्थित परिसर का उपयोग कर सकें। इसके अलावा मूल उप-लीज का विस्तार इस आधार पर किया गया है कि आप उपर्युक्त रेस्तरां को ब्लॉक नंबर 3 के आरएचएस हॉल नंबर 02 में आंतरिक कार्य करने के बाद स्थानांतरित करने के लिए सहमत होंगे क्योंकि यह ब्लॉक नंबर 3 के आरएचएस हॉल नंबर 01 में नहीं किया गया था इसके अलावा, यह विस्तार उन्हीं नियमों और शर्तों पर किया गया है जैसा कि ऊपर उल्लिखित मूल उप-लीज डीड में उल्लेखित और सहमति व्यक्त की गई थी, जो नीचे दिए गए खंड में संशोधन के अधीन है और एक नया खंड/शर्त जोड़ा गया है:

- मूल समझौते के पृष्ठ संख्या 2 पर दिए गए खंड 2 में संशोधन किया गया है और अब इसे इस प्रकार पढ़ा जाएगा: "रेस्तरां के लिए उप-पट्टा किराया खाद्य पदार्थों की बिक्री से प्राप्त कुल राजस्व/बिक्री आय का 30% (जीएसटी को छोड़कर) होगा। उप-पट्टा किराया अगले महीने के पहले सप्ताह तक या उससे पहले भुगतान किया जाएगा"। राजस्व हिस्सेदारी के भुगतान में देरी होने पर, 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा।

- विस्तारित उप-पट्टे में आपसी सहमति से नया खंड/शर्त यह है कि "ब्लॉक संख्या 3 के आरएचएस हॉल संख्या 02 का आंतरिक कार्य पूरा होने के बाद, वर्तमान में ब्लॉक संख्या 03 के आरएचएस हॉल संख्या 01 में चल रहे रेस्तरां को इस विस्तारित उप-पट्टा अवधि के भीतर अर्थात् 30/06/2023 तक ब्लॉक संख्या 3 के आरएचएस हॉल संख्या 02 में स्थानांतरित करना होगा।" और उसके बाद ही नया

पट्टा विलेख निष्पादित किया जा सकता है, या इस पट्टा विलेख को ब्लॉक नंबर 3 के आरएचएस हॉल नंबर 2 में शाकाहारी रेस्तरां चलाने के लिए बढ़ाया जा सकता है।”

मूल उप-पट्टा विलेख के शेष नियम व शर्तें यथावत रहेंगी। कृपया इस पत्र को उप-पट्टा विलेख की अवधि 30 जून 2023 तक बढ़ाने के लिए हमारी (पट्टादाता की) स्वीकृति के प्रतीक के रूप में रखें। मूल उप-पट्टे या संशोधित/नए जोड़े गए खंडों में सहमत किसी भी नियम व शर्त का उल्लंघन उप-पट्टा समझौते को समाप्त कर सकता है, और आपको परिसर खाली करना होगा।

(अंडरलाइन दी गई)

11. आक्षेपित एफआईआर की विषय-वस्तु के आगे अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप यह है कि उप-पट्टा अवधि को 30.06.2023 तक बढ़ाए जाने के बाद, याचिकाकर्ताओं ने राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान करना बंद कर दिया और इसलिए, शिकायतकर्ता द्वारा 01.07.2023 को एक लिखित नोटिस जारी किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा याचिकाकर्ताओं में से एक, श्री गोपाल सिंह को दिनांक 01.07.2023 को जारी किया गया नोटिस भी एक निर्विवाद तथ्य है, इसलिए उप-पट्टा समझौते के निष्पादन से पहले और बाद में पक्षों के इरादों को समझने और याचिकाकर्ताओं द्वारा शुरू से ही प्रलोभन और धोखाधड़ी के आरोपों के संबंध में मामले की जाँच करने के लिए इस नोटिस की विषयवस्तु को पुनः प्रस्तुत करना भी उचित होगा। दिनांक 01.07.2023 का नोटिस इस प्रकार है:

“विषय: दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे (राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे-4), गांव पिनान, जिला अलवर, राजस्थान, पिन कोड 301413, केएम 125 पर स्थित ब्लॉक नंबर 3 के हॉल नंबर 1 के एलएचएस भाग में लीज परिसर को खाली करने का नोटिस” मूल उप-पट्टे के माध्यम से पट्टे पर दिया गया था, जिसे पत्र दिनांक 16/03/2023 के माध्यम से बढ़ाया गया था।

प्रिय महोदय,

यह पत्र आपको सूचित करता है कि आप "दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे (राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे-4), ग्राम पिनान, जिला अलवर, राजस्थान, पिन कोड-301413, किलोमीटर 125 पर स्थित ब्लॉक संख्या 3 के हॉल संख्या 1 स्थित एलएचएस भाग" नामक पट्टे पर दिए गए परिसर को खाली कर दें क्योंकि उप-पट्टे का विस्तार 30/06/2023 को समाप्त हो गया है। इस विस्तारित पट्टे अवधि में, आपका प्रदर्शन असंतोषजनक पाया गया है, क्योंकि आप विस्तारित उप-पट्टे अवधि के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं, जिन्हें निम्नानुसार समझा जा सकता है।

i. हमारे नियमों और शर्तों के अनुसार आपको ब्लॉक नंबर 3 के एलएचएस हॉल नंबर 02 का आंतरिक कार्य पूरा करना था और अपने रेस्तरां को ब्लॉक नंबर 3 के एलएचएस हॉल नंबर 01 से ब्लॉक नंबर 3 के एलएचएस हॉल नंबर 02 में स्थानांतरित करना था। लेकिन आज तक आपके द्वारा कोई काम शुरू नहीं किया गया है।

ii. आप पट्टे की मूल शर्त का पालन करने में भी विफल रहे हैं, अर्थात् अगले महीने के पहले सप्ताह तक या उससे पहले हमें सहमत राजस्व हिस्सेदारी का पूरा भुगतान करना है। उत्पन्न राजस्व की आपकी दैनिक रिपोर्ट के अनुसार, 30/06/2023 तक आपसे कुल 26,79,750/- रुपये की राजस्व हिस्सेदारी देय है।

यह ध्यान रखना उचित है कि एनएचआई (यानी, भारत सरकार) की भी आपके रेस्तरां से उत्पन्न राजस्व में हिस्सेदारी है, इसलिए राजस्व हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा एनएचआई के पास भी जमा करना होगा, जिसका आप पालन करने में विफल रहे हैं। कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त धाराओं का अनुपालन न करने से एनएचआई की विभिन्न सुविधाओं में आपके भविष्य की संभावनाएं प्रभावित हो सकती हैं, जिसमें आपको एनएचआई के साथ उप-अनुबंधित विक्रेता के रूप में ब्लैकलिस्ट करना भी शामिल हो सकता है।

चूंकि विस्तारित लीज अवधि केवल 30/06/2023 तक थी और हम लीज अवधि को और आगे बढ़ाने के इच्छुक/इरादा नहीं रखते हैं, इसलिए आपको "ब्लॉक नंबर 3 के हॉल नंबर 1 के बाएं हिस्से, **KM 125**, दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे (राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे-4), गांव पिनान, जिला अलवर, राजस्थान, पिन कोड-301413 पर स्थित" परिसर को 7 दिनों के भीतर यानी 07/07/2023 को या उससे पहले खाली करना होगा और आपको इस नोटिस की तारीख से 7 दिनों के भीतर **26,79,750/-** रुपये की राजस्व हिस्सेदारी की उपर्युक्त शेष राशि और वास्तविक भुगतान की तारीख तक या जिस तारीख तक रेस्तरां आपके द्वारा चलाया और संचालित किया जाता है, अतिरिक्त राजस्व हिस्सेदारी भी जमा करनी होगी। किसी भी नियम और शर्त का पालन करने में विफल रहने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो सकती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि (1) गणना के अनुसार शेष लीज किराया राशि तुरंत जमा करें और (2) लीज परिसर खाली करें। कृपया इस मामले पर अत्यावश्यक विचार करें।”

12. 11.04.2023 के विस्तार पत्र और 01.07.2023 के नोटिस, जो शिकायतकर्ता द्वारा लिखित है, की विषय-वस्तु को पढ़ने के बाद, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ इस बात का एक शब्द भी नहीं है कि उन्होंने शिकायतकर्ता या जी एंड जी रोड आइलैंड डेवलपर्स एलएलपी के भागीदारों को किसी भी तरह से उप-पट्टा समझौता करने के लिए प्रेरित किया, ताकि वे संबंधित संपत्ति का कब्जा याचिकाकर्ताओं को राजवाड़ा के नाम और शैली में एक शाकाहारी रेस्तरां चलाने के लिए सौंप सकें। यहां तक कि यह भी प्रतिबिंबित हुआ है कि 16.03.2023 से 15.04.2023 तक की प्रारंभिक उप-पट्टा अवधि के लिए पक्षों के बीच सहमत राजस्व को देय नहीं बताया गया था, अर्थात् स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ताओं द्वारा विधिवत भुगतान किया गया था और उप-पट्टे के विस्तार की बाद की अवधि के लिए, आरोप केवल अगले महीने के पहले सप्ताह को या उससे पहले सहमत राजस्व हिस्सेदारी का पूरा भुगतान नहीं करने का है। यद्यपि, इस आधार पर याचिकाकर्ताओं की ओर से यह इंगित करने का प्रयास किया गया है

कि उप-पट्टा अवधि के विस्तार के बाद, 22.06.2023 तक एनईएफटी के माध्यम से शिकायतकर्ता के खाते में समय-समय पर राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान किया गया और कुल 78,29,335/- रुपये का भुगतान किया गया है। फिर भी, यह न्यायालय राजस्व हिस्सेदारी के देय बकाया की राशि के संबंध में पक्षों के बीच विवाद के ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने से खुद को रोक रहा है, जिसके लिए यह विवादित नहीं किया जा सकता है कि यदि राजस्व की कोई बकाया राशि देय हो जाती है, तो याचिकाकर्ता भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे/हैं, लेकिन यह वर्तमान याचिकाओं के दायरे में नहीं है। यह न्यायालय इस बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है कि क्या याचिकाकर्ताओं का इरादा शुरू से ही धोखाधड़ी और छलपूर्ण था और याचिकाकर्ताओं ने किसी भी तरह से शिकायतकर्ता को उप-पट्टा समझौते में प्रवेश करने और शाकाहारी रेस्तरां चलाने के उद्देश्य से संबंधित संपत्ति का कब्जा सौंपने के लिए प्रेरित किया।

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा संदर्भित विजय कुमार घई (सुप्रा) मामले में, भारतीय दंड संहिता की धारा 405-आपराधिक विश्वासघात और धारा 415-धोखाधड़ी के प्रावधानों पर विचार किया। कानून के इन प्रावधानों के अंतर्गत अपराध गठित करने हेतु आवश्यक तत्वों पर चर्चा के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा संख्या 28 और 31 में निम्नलिखित टिप्पणी की:

"28. कपटपूर्ण या बेईमानी से किया गया प्रलोभन इस अपराध का एक अनिवार्य घटक है। जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को संपत्ति सौंपने के लिए बेईमानी से प्रेरित करता है, वह धोखाधड़ी के अपराध के लिए उत्तरदायी है।

31. संपत्ति सौंपने के लिए प्रेरित करने में धोखाधड़ी के अपराध को सिद्ध करने के लिए, निम्नलिखित घटकों को सिद्ध करना आवश्यक है:

1. व्यक्ति द्वारा किया गया अभ्यावेदन झूठा था।

2. अभियुक्त को पहले से पता था कि उसके द्वारा किया गया अभ्यावेदन झूठा था।
3. अभियुक्त ने उस व्यक्ति को धोखा देने के लिए बेईमानी से झूठा अभ्यावेदन किया, जिसे यह अभ्यावेदन दिया गया था।
4. वह कार्य जिसमें अभियुक्त ने व्यक्ति को संपत्ति सौंपने या ऐसा कोई कार्य करने या उससे विरत रहने के लिए प्रेरित किया, जो व्यक्ति ने अन्यथा नहीं किया होता या किया होता।”

सरबजीत कौर (सुप्रा) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय, पक्षों के बीच हुए अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन के कारण, भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 120-बी और 406 के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के मुद्दे पर विचार कर रहा था। ऐसी तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा संख्या 13 में निम्नलिखित टिप्पणी की:

“13. अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने का कारण नहीं बनता, जब तक कि लेन-देन की शुरुआत में ही धोखाधड़ी या बेईमानी का इरादा न दिखाया गया हो। केवल वादा पूरा न करने के आरोप के आधार पर आपराधिक कार्यवाही शुरू करना पर्याप्त नहीं होगा। अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने पहली शिकायत दर्ज होने के बाद से ही अपने मामले में सुधार किया था, जिसमें अपीलकर्ता के खिलाफ कोई आरोप नहीं थे, बल्कि केवल प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ आरोप थे, और बाद की शिकायतों में अपीलकर्ता का नाम आया था। पहली शिकायत में, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा भुगतान की गई राशि की वापसी का एकमात्र अनुरोध था। जब पहली शिकायत के आधार पर अपराध सिद्ध हुआ, तो दूसरी शिकायत में सुधार करके अपीलकर्ता के खिलाफ भी आरोप लगाए गए, जो पिछली शिकायत में नहीं थे। ऐसा लगता है कि पूरा उद्देश्य एक दीवानी विवाद को आपराधिक विवाद में बदलना और अपीलकर्ता पर कथित रूप से भुगतान की गई राशि वापस पाने के लिए दबाव डालना है। आपराधिक अदालतों का उपयोग बदला लेने या पक्षकारों पर दीवानी विवादों को निपटाने

के लिए दबाव डालने के लिए नहीं किया जाता है। जहाँ भी आपराधिक अपराध के तत्व सामने आने पर, आपराधिक अदालतों को संज्ञान लेना होगा। जिस शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी, वह बिक्री विलेख के पंजीकरण की अंतिम तिथि के लगभग तीन साल बाद दर्ज की गई थी। कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

14. एफआईआर में शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए तथ्यात्मक आरोपों और शिकायतकर्ता द्वारा शामिल किए गए बचावों पर ध्यान देने के बाद, 11.04.2023 के विस्तार पत्र के माध्यम से उप-पट्टे की अवधि बढ़ाते समय और राजस्व हिस्सेदारी के भुगतान में चूक के कारण उप-पट्टा क्षेत्र को खाली करने की मांग करने के लिए 01.07.2023 को नोटिस जारी करते समय और विस्तारित उप-पट्टा अवधि के अन्य नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने के संबंध में, यह कहीं भी नहीं दर्शाता है कि शिकायतकर्ता को याचिकाकर्ताओं द्वारा किसी भी तरह से, वह भी धोखाधड़ी और बेईमान इरादे से, उप-पट्टा समझौते में प्रवेश करने या पार्टियों के बीच सहमति के अनुसार उप-पट्टे के नियमों और शर्तों को निपटाने या शाकाहारी रेस्तरां चलाने के लिए संबंधित संपत्ति का कब्जा देने के लिए प्रेरित किया गया था। भले ही शिकायतकर्ता का मामला, जैसा कि रिकॉर्ड में रखे गए अन्य दस्तावेजों के समर्थन में एफआईआर में रखा गया है, उसके अंकित मूल्य पर लिया जाता है पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच के बाद विद्वान लोक अभियोजक द्वारा दिनांक 05.12.2023 को रिकार्ड पर रखी गई स्थिति रिपोर्ट में, इस बात पर टिप्पणी करने के लिए किसी भी सामग्री का संदर्भ या भरोसा नहीं है कि किस आधार पर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 406 और 120-बी के तहत अपराध स्थापित किए गए हैं। यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एफआईआर में केवल "धोखा", "धोखाधड़ी" या "आपराधिक विश्वासघात" शब्दों का इस्तेमाल ऐसे अपराधों का गठन करने के

लिए पर्याप्त नहीं है और जब तक एफआईआर की सामग्री से या जांच के दौरान पहली नजर में कुछ ऐसा नहीं निकलता है कि याचिकाकर्ताओं ने संपत्ति सौंपने के लिए शुरुआत में ही धोखाधड़ी की थी, बिना किसी आधारभूत सामग्री के जांच एजेंसी का केवल अनुमान, कानून के मापदंडों के भीतर आपराधिक प्रस्ताव को स्वीकार करने और एफआईआर और जांच को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है, खासकर जब यह अपने प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि अपराध के किए जाने को स्थापित करने के लिए आवश्यक तत्व अनुपस्थित हैं। स्थिति रिपोर्ट के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि जांच एजेंसी ने बिना किसी विशिष्ट कारण बताए, जांच के लिए याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार करने की आवश्यकता पर राय दी है इसलिए, ऐसी परिस्थितियों में, यह देखा जा सकता है कि जांच एजेंसी द्वारा धारा 41-ए सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी करना महज दिखावा प्रतीत होता है और प्रावधान के उद्देश्य के अनुरूप नहीं है।

ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस की सहायता से शिकायतकर्ता किसी न किसी कारण से आपराधिक कार्रवाई जारी रखने का इरादा रखता है, जाहिर तौर पर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अपने लक्ष्य/उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उन पर अनुचित दबाव डालकर, आक्षेपित एफआईआर पर जांच लंबित रखने के लिए। आपराधिक कार्रवाई की कार्रवाई को केवल आरोपी व्यक्तियों पर दबाव डालने या उन्हें परेशान करने के लिए शुरू करने या जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न घोषणाओं की मदद से ऊपर चर्चा की गई है कि यदि एफआईआर और उसके बाद की जांच, चौधरी भजनलाल (सुप्रा) के ऐतिहासिक फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड से कम पाई जाती है, तो उच्च न्यायालय एफआईआर और उसके बाद होने वाली

आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तत्काल संदर्भ के लिए, उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग अर्थात पैरा संख्या 102 और उप-पैरा संख्या 102(3) नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

“102. अध्याय XIV के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति या संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, जिन्हें हमने ऊपर उद्धृत और पुनः प्रस्तुत किया है, हम उदाहरण के तौर पर मामलों की निम्नलिखित श्रेणियां देते हैं जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि किसी भी सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से चैनलाइज्ड और अनम्य दिशानिर्देश या कठोर फॉर्मूले को निर्धारित करना संभव नहीं हो सकता है और असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं है जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

.....

3. जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उनके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के किए जाने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं।

वर्तमान मामले के तथ्य, उच्च न्यायालय द्वारा निहित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए ऐसे मानदंडों को लागू करने को आमंत्रित करते हैं।

15. जहां तक शिकायतकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों का संबंध है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह न्यायालय पाता है कि पक्षों के बीच निष्पादित पिछले दस्तावेजों, जिसमें उप-पट्टा समझौता, विस्तार पत्र और शिकायतकर्ता द्वारा जारी नोटिस शामिल हैं, जो कि कथित एफआईआर दर्ज करने से

पहले के हैं, के अवलोकन से याचिकाकर्ताओं द्वारा शिकायतकर्ता पर किसी भी तरह के प्रलोभन का कोई संकेत या एक शब्द भी नहीं मिलता है, वह भी शुरुआत से ही संपत्ति का कब्जा लेने के बेईमान और दुर्भावनापूर्ण इरादे से, यानी उप-पट्टा समझौते में प्रवेश करते समय या उसके बाद भी। यह शिकायतकर्ता का एक स्वीकृत मामला है जो उप-पट्टा अवधि के विस्तार पत्र दिनांक 11.04.2023 और दिनांक 01.07.2023 के नोटिस के अवलोकन से दर्शाता है कि जिन नियमों और शर्तों पर विश्राम क्षेत्र (यहां विचाराधीन संपत्ति) का कब्जा याचिकाकर्ताओं को सौंपा गया था, वे पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से तय किए गए थे। शिकायतकर्ता का सबसे अच्छा मामला, अधिक से अधिक, याचिकाकर्ताओं द्वारा उप-पट्टा समझौते में शामिल सहमत नियमों और शर्तों का उल्लंघन करना है, जैसा कि विस्तार पत्र में भी है। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ शुरू से ही प्रलोभन और बेईमान इरादे रखने के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन संबंधित एफआईआर दर्ज करने से पहले, पक्षों के बीच निष्पादित पिछले दस्तावेजों से इनकी कोई पुष्टि और समर्थन नहीं मिलता है। इस तरह के आरोप, वर्तमान मामले के अजीबोगरीब तथ्यों की पृष्ठभूमि में, बाद में लगाए गए और हवा में उठाए गए प्रतीत होते हैं, संभवतः किसी कानूनी विशेषज्ञ की मदद से और मूल और सच्चे तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। इसलिए, केवल इस तरह के बाद के विचारों और निराधार आरोपों के आधार पर, शिकायतकर्ता का मामला एक वैध आपराधिक प्रस्ताव के मापदंडों के अंतर्गत आता है।

उमा शंकर गोपालिका (सुप्रा) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एफआईआर को रद्द करने के एक मामले पर विचार करते हुए, इस तथ्य की पृष्ठभूमि में कि वित्त कंपनी ने बीमा कंपनी से वित्तपोषित वाहन पर दावा प्राप्त करने के बावजूद, शिकायतकर्ता को मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं किया, वित्त कंपनी द्वारा उसे दिए गए आश्वासन के बावजूद, जिसके कारण शिकायतकर्ता ने वित्त कंपनी

पर धोखाधड़ी का मुकदमा चलाने के लिए आपराधिक शिकायत दर्ज कराई, यह माना गया कि "यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अनुबंध का प्रत्येक उल्लंघन धोखाधड़ी के अपराध को जन्म नहीं देगा और केवल उन मामलों में अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के बराबर होगा जहां शुरू से ही कोई धोखा हुआ था। यदि धोखा देने का इरादा बाद में विकसित हुआ है, तो इसे धोखाधड़ी नहीं माना जा सकता है।" (रेखांकन मेरे हैं)। कानून के ऐसे सिद्धांत को लागू करते हुए, जिसका पालन सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2022 में विजय कुमार घई (सुप्रा) के मामले में किया है, वर्तमान मामले के तथ्यों पर, एफआईआर या जांच रिपोर्ट से रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि शुरू से ही, उप-पट्टा समझौते में प्रवेश करते समय या उप-पट्टा अवधि के विस्तार के समय, याचिकाकर्ताओं का धोखा देने का कोई बेईमान इरादा था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि याचिकाकर्ताओं ने उप-पट्टा अवधि के विस्तार के बाद राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान करना बंद कर दिया और 01.07.2023 को नोटिस जारी करने के बावजूद खाली कब्जा सौंपने से इनकार कर दिया, भले ही इसे वैसे ही स्वीकार किया जा सकता है, वही अधिक से अधिक राजस्व हिस्सेदारी के बकाया और याचिकाकर्ताओं द्वारा कब्जा न देने के बारे में पक्षों के बीच विवाद को जन्म देता है, और विवाद की ऐसी प्रकृति, मुख्य रूप से पक्षों के बीच नागरिक विवाद के दायरे में आती है। शुरू से ही याचिकाकर्ताओं की ओर से किसी भी तरह के बेईमान इरादे या प्रलोभन के अभाव में, जो कि आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत अपराध गठित करने के लिए पूर्व शर्त हैं, याचिकाकर्ताओं को शिकायतकर्ता की इच्छा के आधार पर गुप्त मकसद से आपराधिक कार्रवाई शुरू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। वास्तव में, मामले के ऐसे अजीबोगरीब तथ्यों की पृष्ठभूमि में, पक्षकारों के लिए सिविल फोरम का दरवाजा खटखटाना ही उपाय है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उमा शंकर गोपालिका (सुप्रा) में स्पष्ट रूप से कहा कि

“हमारी राय में, इन तथ्यों के मद्देनजर पुलिस जांच जारी रखने की अनुमति देना अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और इसे रोकने के लिए यह उचित और समीचीन था कि उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके इसे रद्द कर दे, जिसे उसने गलती से अस्वीकार कर दिया है।”

इसलिए, यह न्यायालय वर्तमान मामले को धारा 482 सीआरपीसी के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक असाधारण और उपयुक्त मामला मानता है ताकि आक्षेपित एफआईआर और उसके आधार पर जांच को रद्द किया जा सके।

16. शिकायतकर्ता के विद्वान वकील का यह तर्क कि विस्तारित उप-पट्टा समझौते के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के संबंध में केवल सिविल उपाय की उपलब्धता, शिकायतकर्ता को आपराधिक कार्यवाई शुरू करने से नहीं रोकती है और सिविल के साथ-साथ आपराधिक कार्यवाही भी साथ-साथ चल सकती है, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा खारिज नहीं किया गया है। कानूनी प्रस्ताव के बारे में कोई संदेह/विवाद नहीं है। इसी तरह, कानून का प्रस्ताव कि आपराधिक अभियोजन को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि विवाद को निपटाने के लिए पक्षों के बीच लिखित समझौते में मध्यस्थता का खंड मौजूद है जैसा कि शिकायतकर्ता के वकील द्वारा संदर्भित टिसन्स केमिकल इंडस्ट्री (सुप्रा), लालमुनि देवी (सुप्रा) और उज्ज्वल कुमार बर्धन (सुप्रा) के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है, भी विवाद में नहीं है। कानून के ऐसे प्रस्ताव के बारे में कोई झगड़ा नहीं है कि सिविल और आपराधिक कार्यवाही एक साथ चल सकती लेकिन वर्तमान मामलों के तथ्यात्मक मैट्रिक्स की सराहना करने पर, एफआईआर के बचावों को ध्यान में रखते हुए भी, प्रारंभिक जांच के बाद जांच एजेंसी की स्थिति रिपोर्ट, पार्टियों के बीच निष्पादित पिछले निर्विवाद दस्तावेजों के साथ, प्रथम दृष्टया विस्तार पत्र में इंगित शर्तों सहित उप-पट्टा समझौते की शर्तों और नियमों का

पालन न करने के लिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कोई अपराध नहीं बनता है, भले ही याचिकाकर्ताओं को तर्क के लिए डिफॉल्टर माना जाता है। इस न्यायालय की राय में जब प्रथम दृष्टया एफआईआर में किए गए बचावों और आरोपों से और समग्रता में सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, किसी भी अपराध का कमीशन नहीं बनता है और न ही घटनाओं की पूरी श्रृंखला जैसा कि शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया है, याचिकाकर्ताओं द्वारा किसी भी अपराध का कमीशन प्रकट होता है, फिर धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के अपराधों के लिए याचिकाकर्ताओं पर मुकदमा चलाने के लिए न्याय का उपहास होगा। ऐसी परिस्थितियों और विचित्र तथ्यों में, एफआईआर दर्ज करना और उसके बाद पुलिस कर्मियों द्वारा जांच की अनुमति देना न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के समान नहीं होगा, बल्कि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

17. यह न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एम.एन. ओझा बनाम आलोक कुमार श्रीवास्तव [(2009) 9 एससीसी 682] के मामले में की गई टिप्पणियों को पुनः प्रस्तुत करना उचित और लाभप्रद पाता है। यह टिप्पणी उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक कार्यवाही समाप्त करने के लिए निहित शक्तियों का प्रयोग न करने के मामले पर विचार करते समय की गई थी, जबकि यह तर्क दिया गया था कि शिकायतकर्ता द्वारा आपराधिक याचिका शुरू करने का उद्देश्य अभियुक्तों पर दबाव डालना और उन्हें परेशान करना था। सुलभ संदर्भ के लिए, उक्त निर्णय के प्रासंगिक अंश, अर्थात् पैरा संख्या 29, 30, 31 और 32, नीचे पुनः प्रस्तुत किए जा रहे हैं:

"29. यह सत्य है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए न्यायालय आरोपों की सत्यता या असत्यता की जाँच नहीं कर सकता और अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों का

मूल्यांकन नहीं कर सकता। सामान्यतः, उच्च न्यायालय प्रारंभिक जाँच/जाँच लंबित होने पर/जब...

30. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप केवल तभी किया जा सकता है जब ऐसे हस्तक्षेप का स्पष्ट मामला बनता हो। उच्च न्यायालय द्वारा प्रारंभिक चरण में भी बार-बार और अनावश्यक हस्तक्षेप करने से किसी आपराधिक मामले में जाँच की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो सकती है जो जनहित में नहीं हो सकती है। लेकिन साथ ही, उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार नहीं कर सकता यदि न्याय के हित में ऐसा आवश्यक हो, जहाँ प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हों कि कोई भी निष्पक्ष और जानकार पर्यवेक्षक कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधारों के अस्तित्व के बारे में कभी भी उचित और न्यायसंगत निष्कर्ष पर न पहुँच सके। ऐसे मामलों में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार करने से समान रूप से अन्याय हो सकता है, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जहाँ ऐसे मामले जहाँ शिकायतकर्ता, शिकायत में अभियुक्त बनाए गए व्यक्तियों पर दबाव डालने और उन्हें परेशान करने के उद्देश्य से आपराधिक कानून को लागू करता है।

31. यह सर्वविदित है और इसमें पुनः कथन की आवश्यकता नहीं है कि आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का संरक्षण एक हितकारी सार्वजनिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है।

‘अर्थात् अदालती कार्यवाही को उत्पीड़न या उत्पीड़न के हथियार में बदलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। [यदि ऐसी शक्ति को स्वीकार नहीं किया जाता है, तो इससे अन्याय भी हो सकता है]’।

32. हम जानते हैं कि

‘अंतर्निहित शक्तियां उच्च न्यायालय को "अपनी इच्छा या सनक के अनुसार कार्य करने" का मनमाना अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती हैं। उस वैधानिक शक्ति का प्रयोग संयम से, सावधानी के साथ और अत्यंत दुर्लभ मामलों में ही किया जाना चाहिए।”

18. इस प्रकार, ऊपर वर्णित घटनाओं के क्रम का विस्तार से उल्लेख करने और समग्र रूप से विचार करने के बाद, यह न्यायालय इस दृढ़ राय का है कि याचिकाकर्ताओं ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का आह्वान करने के लिए एक असाधारण मामला बनाया है। आरोपित प्राथमिकी का पंजीकरण और उसके बाद जांच जारी रखना प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग पाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ताओं पर दबाव बनाने और उन्हें परेशान करने के उद्देश्य से आपराधिक याचिका शुरू की है और उन्हें आक्षेपित प्राथमिकी में आरोपी बनाया है। पक्षों के बीच विवाद, अधिक से अधिक, मुख्य रूप से एक दीवानी प्रकृति का विवाद पाया गया है, जिसे आपराधिक रंग देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए, वर्तमान मामलों में, आरोपित प्राथमिकी को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार करना, याचिकाकर्ताओं के साथ समान रूप से अन्याय होगा और न्याय की विफलता का कारण बनेगा।

19. अंतिम परिणाम के रूप में, ये तीनों याचिकाएँ सफल होती हैं और पुलिस स्टेशन मालवीय नगर, जिला जयपुर में धारा 420, 406 और 120-बी आईपीसी के तहत दर्ज की गई एफआईआर संख्या 361/2023 और उसके बाद की सभी कार्यवाहियों को कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग घोषित किया जाता है और इसलिए इन्हें निरस्त किया जाता है।

20. स्थगन आवेदन और अन्य लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा किया जाता है।

21. इस निर्णय की एक प्रति प्रत्येक संबद्ध फाइल में रखी जाए।

(सुदेश बंसल), न्यायमूर्ति

### सचिन

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निशपादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी